दैनिक जागरण
बाधा जितनी बड़ी होती है, विजय भी उतनी ही बड़ी होती है

दोहरी चुनौती

सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के इस कथन पर हैरानी नहीं कि पाकिस्तान कश्मीर में हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान यह काम न जाने कब से कर रहा है, लेकिन जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वह घाटी में आतंक फैलाने पर कुछ ज्यादा ही आमादा है। कश्मीर में दबे-छिपे आतंकियों की ओर से गैर कश्मीरियों को चुन-चुन कर निशाना बनाने और व्यापारियों को धमकाने के मामले यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। इसी बौखलाहट में वह संघर्ष विराम का रह-रहकर उल्लंघन करने में लगा हुआ है। चूंकि इस सबके साथ वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार भी छेड़े हुए है इसलिए भारत के सामने दोहरी चुनौती है। भारत को एक ओर कश्मीर में पाकिस्तान पोषित-प्रेरित आतंकियों से निपटना है और दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसके दुष्प्रचार की काट भी करनी है। यह चुनौती इसलिए और बढ़ गई है, क्योंकि कश्मीर को रही-सही पाबंदियों से मुक्त करने की मांग भी तेज हो रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही इस मांग का एक बड़ा कारण अमेरिकी, ब्रिटेन सरीखे देशों के साथ विश्व समुदाय का इससे अनभिज्ञ होना है कि कश्मीर समस्या वास्तव में है क्या? मलेशिया और तुर्की की ओर से कश्मीर को लेकर दिए गए बयानों ने इस अनभिज्ञता को ही रेखांकित किया।

पिछले दिनों अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की एक समिति में हुई चर्चा ने यही प्रकट किया कि अमेरिका कश्मीर पर सतही जानकारी ही रखता है। यही कारण रहा कि इस चर्चा के बाद भारत को यह कहना पड़ा कि अमेरिकी सांसद भारतीय लोकतंत्र के बारे में पर्याप्त समझ नहीं रखते। समझ के इस अभाव के लिए कहीं न कहीं वह नीति जिम्मेदार है जिसके तहत अभी हाल तक भारत कश्मीर को लेकर रक्षात्मक रवैया अपनाए रहा। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कश्मीर के मामले में खलनायक होने के बाद भी पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह प्रतीति कराता रहा कि उसे भारत के इस हिस्से में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। यह एक विडंबना ही रही कि पाकिस्तान तो कश्मीर के हालात को लेकर दुनिया भर में हल्ला मचाता रहा, लेकिन भारत ने गुलाम कश्मीर की दयनीय दशा को कभी मुद्दा नहीं बनाया। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि पाकिस्तान का छल-कपट हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेनकाब हो। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि दिवाली के दिन लंदन में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान प्रायोजित आयोजन पर भारत ने अपनी चिंता जताई। भारत को इसके आगे तक जाना चाहिए और ऐसे भारत विरोधी आयोजनों पर ब्रिटिश सरकार से कड़ी आपत्ति जतानी चाहिए।

उत्तराखंड की जल नीति

उत्तराखंड में प्राकृतिक स्रोतों से जल संरक्षण और इसके किफायती इस्तेमाल को लेकर जल नीति का बनाया जाना एक अच्छा कदम है। बशर्ते संबंधित विभाग इस नीति को ईमानदारी से धरातल पर उतारने का प्रयास करें। यह सवाल इसलिए उठाया जा रहा है, क्योंकि पूर्व में भी सरकारों ने जल संरक्षण को लेकर कई कदम उठाए, लेकिन इनमें गंभीरता से काम न होने के कारण ये पूरी तरह परवान नहीं चढ़ पाए। प्रदेश में लगातार गहराते जल संकट को देखते हुए सरकार ने अब बैठकों और घोषणाओं से आगे बढ़ते हुए नीति का स्वरूप तय कर दिया है। दरअसल देखा जाए तो इस समय प्रदेश में जल संकट गहराने लगा है। चाहे पहाड़ी क्षेत्र हों अथवा मैदानी, सभी जगह पानी के मामले में स्थिति तकरीबन एक जैसी ही है। पहाड़ों में जल स्रोतों के सूखने तो मैदानी क्षेत्रों में भूजल के अनियंत्रित दोहन से यह परेशानी बढ़ी है। यह अच्छी बात रही कि सरकार ने इस पर चिंतन मनन किया और जल नीति को आकार दिया। इस नीति में जलस्रोतों के पुनर्जीवीकरण पर खास फोकस किया गया है। इसके लिए बारिश के पानी को सहेजने के लिए परंपरागत तौर तरीकों खाल-चाल यानी छोटे-बड़े तालाबनुमा गड्ढों को शामिल किया गया है। जलस्रोतों के कैचमेंट एरिया में जल संरक्षण में सहायक पौधे लगाए जाएंगे। पहले ये चाल-खाल ही जलस्रोतों के निरंतर बहाव में सहायक होते थे। इनके समाप्त होते ही प्राकृतिक जल स्रोत भी सूखने लगे हैं।

> प्रदेश सरकार ने जल नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब आमजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है

नीति में झरनों के पुनर्जीवीकरण के साथ ही कृषि में सूक्ष्म सिंचाई, ग्रेविटी आधारित पेयजल योजनाओं को महत्व दिया गया है। किफायत से पानी का इस्तेमाल, अनियंत्रित भूजल के दोहन पर अंकुश लगाना, वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए कदम उठाना, छोटी जल विद्युत परियोजनाएं और घराट को तवज्जो दिए जाने समेत कई अन्य बिंदु शामिल हैं। इसके साथ ही जल आवंटन की प्राथमिकता, भूजल के उपयोग, सिंचाई, ईको टूरिज्म आदि में वाटर चार्ज लगाने की व्यवस्था भी इस नीति में की गई है। नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब सरकार को चाहिए कि वह इसे पूरी गंभीरता के साथ धरातल पर उतारे। इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। इसके साथ ही आमजन को भी जल संरक्षण और इसके किफायती इस्तेमाल के प्रति जागरूक करने के लिए नीति का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए।

भाजपा की कमजोर कड़ी

डॉ. एके वर्मा

दो राज्यों के चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि शासन और शुचिता के जो प्रतिमान मोदी ने स्थापित किए हैं उनसे राज्यों में भाजपा सरकारों के मंत्री दूरी बनाए हुए हैं

महाराष्ट्र, हरियाणा विधानसभा और 17 राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों की 51 विधानसभा और दो लोकसभा सीटों के नतीजे राजनीतिज्ञों, बुद्धिजीवियों और सामान्य जनता के बीच चर्चा के केंद्र में हैं। हरियाणा के नतीजों को लेकर ज्यादा चर्चा होना स्वाभाविक है। 1 नवंबर 1966 को गठित हरियाणा में पहला विधानसभा चुनाव 1967 में चुनाव हुआ था। तब से कुछ अपवादों को छोड़कर वहां कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा। 2014 में मोदी लहर में वह वर्चस्व टूट गया। यहां पहली बार भाजपा की सरकार तो बनी ही, एक गैर-जाट मनोहरलाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि हरियाणा की राजनीति में आज तक कोई भी मुख्यमंत्री रहते हुए अगला कार्यकाल नहीं पा सका है। यदि मनोहरलाल पुनः मुख्यमंत्री बनते हैं जो कि तय दिख रहा है तो यह भी एक इतिहास ही होगा। ज्यादातर लोग केवल राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त सीटों पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन जनसमर्थन का एक और पहलू मत-प्रतिशत होता है। भाजपा को हरियाणा में 2014 के मुकाबले सात सीटें जरूर कम मिली हैं, लेकिन उसे 3.3 प्रतिशत ज्यादा मत मिले हैं। स्पष्ट है कि भाजपा का राज्य में जनाधार बढ़ा है। यह भी रेखांकित किया जाना जरूरी है कि हरियाणा की छह सीटों पर हार-जीत 2000 से कम वोटों से हुई। तीन सीटों पर तो 1000 से कम मतों से हार-जीत हुई। निःसंदेह इसका यह मतलब नहीं कि खट्टर सरकार में सब कुछ ठीक-ठाक रहा। ऐसा रहा होता तो कांग्रेस ने हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया होता। उसने 2014 की 15 सीटों के मुकाबले दोगुनी अर्थात 31 सीटें जीतीं। कृषि-प्रधान हरियाणा में खट्टर सरकार द्वारा किसानों के मसले अपेक्षित गंभीरता से हल नहीं किए गए, चाहे वह फसलों की खरीद का मसला रहा हो या समर्थन मूल्य का अथवा पराली की समस्या। इसी के साथ यह भी स्वीकार करना होगा कि हरियाणा की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति भी उसकी कुछ समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। राजनीतिक नफा-नुकसान के कारण कोई भी सरकार हस्तक्षेप करने से कतराती है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को 50 हजार मतों से और साथ ही हरियाणा के 10 मंत्रियों में से 8 को हराकर जनता ने खट्टर सरकार को यही संदेश दिया कि पार्टी और सरकार, दोनों ही स्तरों पर बदलाव और सुधार की बेहद जरूरत है। 'जाट-फैक्टर' प्रदेश की राजनीति में हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और नेतृत्व में जाटों को सर्वोपरि न रखना भी उनकी भाजपा से नाराजगी का कारण रहा। इसीलिए सोनीपत से लेकर सिरसा तक 'जाट-बेल्ट' में कांग्रेस का वर्चस्व रहा और भाजपा की करारी शिकस्त हुई और वह भी तब जब यहां कई जगह भाजपा के प्रत्याशी जाट ही थे। कुछ महीने पूर्व लोकसभा चुनावों में जब जाट नेतृत्व का मुद्दा नहीं था तब भाजपा ने जाट-बेल्ट में अपना दबदबा कायम रखा था।यह देखना मनोरंजक होगा कि पार्टी आगे कैसे जाट और गैर-जाट के बीच समन्वय करती है? यही भाजपा और हरियाणा की भावी राजनीति को परिभाषित करेगा, लेकिन हरियाणा में मात्र 11 महीने पुरानी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी (जजपा) की 10 सीटों की अप्रत्याशित जीत प्रदेश की राजनीति में एक नए खिलाड़ी का संकेत दे रही है। इसी के प्रतिकूल मीडिया और सोशल मीडिया में उपस्थिति के बावजूद योगेंद्र यादव की स्वराज्य इंडिया कोई प्रभाव नहीं दिखा सकी।

महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा और कुछ अपवादों को छोड़ साथ-साथ नजर आईं। उनकी विजय भी हुई, लेकिन 2014 की अपेक्षा कुछ कम सीटें मिलीं। हालांकि चुनावों के पूर्व शरद पवार की पार्टी राकांपा से जिस तरह भाजपा की ओर भगदड़ देखी गई उससे ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र में पवार का अस्त निकट है, लेकिन उम्र की इस दहलीज पर भी उन्होंने जिस तरह धुआंधार चुनाव प्रचार किया और किसानों की समस्याओं, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी आदि मुद्दों को शिद्दत से उठाया वह काबिले तारीफ रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने उन सभी की हार सुनिश्चित करने की भी रणनीति बनाई जो राकांपा छोड़कर चले गए थे। इनमें छत्रपति शिवाजी के वंशज भी शामिल हैं। 2014 के मुकाबले 13 सीटें अधिक जीत कर 54 सीटों के साथ राकांपा कांग्रेस की 44 सीटों से काफी आगे निकल गई। इस प्रकार महाराष्ट्र की राजनीति में पवार का पुनः अभ्युदय हुआ। महाराष्ट्र की राजनीति में वैसे तो तस्वीर साफ है, लेकिन शिवसेना के अपने गुप्त दांव हैं। वह स्वयं को सदैव एक 'किंगमेकर' की भूमिका में रखना चाहती है।

महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए होती हैं। कांग्रेस और राकांपा को मिला कर 100 सीटें ही हैं। यदि उसे शिवसेना की 54 सीटें मिल जाएं तो राज्य में गैरभाजपा सरकार बन सकती है। इसे हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता, क्योंकि शिवसेना ने भाजपा को अनेक शर्तों से बांध रखा है। शिवसेना एक तो फड़नवीस सरकार में 50-50 प्रतिशत की हिस्सेदारी चाहती है और यह भी कि मुख्यमंत्री ढाई वर्ष भाजपा का और ढाई वर्ष शिवसेना का हो। वह आगामी बीएमसी के चुनावों में अग्रणी भूमिका को लेकर भी प्रतिबद्ध है। शिवसेना मोदी मंत्रिमंडल में और स्थान चाहती है। इसके अलावा वह लोकसभा का उपसभापति पद भी चाहती है। उसकी यह चाहत भाजपा के लिए समस्या बना सकती है। जो भी हो, महाराष्ट्र में पवार के साथ-साथ 'ठाकरेवाद' का भी अभ्युदय देखा जा सकता है। कांग्रेस की भी इसमें दिलचस्पी हो सकती है कि पवार-ठाकरे के रूप में क्षेत्रीय शक्तियों को जोड़ कर राज्य की राजनीति से भाजपा को बाहर किया जाए, भले ही उसमें उसका नुकसान हो। यह नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव पूर्व गठबंधन के बावजूद शिवसेना और भाजपा ने एक-दूसरे को पीछे धकेलने में कोई कमी नहीं छोड़ी। संभवतः आरएसएस ने भी भाजपा के बागियों की जीत में अहम भूमिका निभाई, अन्यथा देवेंद्र फड़नवीस के शहर में भाजपा करीब 50 प्रतिशत सीटें हारती नहीं।

महाराष्ट्र में भाजपा के 15 बागी विधायक बन गए हैं। भाजपा की विदर्भ में हार नितिन गडकरी के रोष और चीनी-पट्टी पश्चिम-महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन मराठा की नाराजगी की वजह से संभव है, लेकिन हरियाणा की ही तर्ज पर महाराष्ट्र में भी आठ मंत्री हार गए जो पुनः रेखांकित करता है कि जमीनी स्तर पर सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में मंत्रीगण कुछ खास रुचि नहीं ले रहे हैं। यह बात उन सभी राज्यों में भी लागू होती है जहां भाजपा की सरकारें हैं। लोग मोदी से खुश हैं, लेकिन शासन और शुचिता के जो प्रतिमान उन्होंने स्थापित किए उनसे राज्यों में भाजपा सरकारों के मंत्री दूरी बनाए हुए हैं। यह भाजपा के लिए एक चुनौती है। उसे इस चुनौती का सामना गंभीरता से करना होगा। अगर इसमें ढिलाई बरती गई तो विपक्ष उस पर भारी पड़ सकता है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं)

response@jagran.com

राष्ट्रव्यापी समस्या बनता प्रदूषण

प्रियंका मलिक

> यह खौफनाक है कि दुनिया भर में प्रदूषण की वजह से मरने वालों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है

दशहरे के समय दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण की जिस समस्या ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू किया था वह दिवाली आते-आत और अधिक गंभीर रूप लेती दिख रही है। अंदेशा है कि दिवाली के बाद प्रदूषण में और वृद्धि हो सकती है। इसका कारण पराली जलना तेज होना, तापमान में गिरावट आना और दिवाली पर पटाखे छोड़े जाना है। यह एक तथ्य है कि बीते कुछ दिनों से दिल्ली के साथ-साथ उत्तर भारत के अन्य शहरों में वायु की गुणवत्ता में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वायु प्रदूषण हमारे शहरों की एक स्थाई समस्या बनता जा रहा है। आम तौर पर गर्मी में प्रदूषण का दोष राजस्थान-पाकिस्तान से आने वाली धूल को दे दिया जाता है और ठंड में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों को। हालांकि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई तरह की कोशिश की गई हैं, लेकिन वे एक हद तक ही कामयाब हुई हैं। भले ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर एनजीटी तक का ध्यान केंद्रित रहता हो, लेकिन सच्चाई यह है कि दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत के शहरों का हाल काफी कुछ दिल्ली जैसा ही है। जहां दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण चर्चा का विषय बनता है वहीं अन्य शहरों में प्रदूषण की गंभीरता को लेकर कोई ठोस चर्चा भी नहीं हो पाती।

हालांकि दूषित होता पर्यावरण विश्वव्यापी समस्या है, परंतु जिन देशों में उसकी गंभीरता भयावह रूप लेती जा रही है उनमें भारत भी है। यह खौफनाक है कि दुनिया भर में प्रदूषण की वजह से मरने वालों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। पिछले साल आई क्यूएअर विजुवल और ग्रीन पीस की रिपोर्ट ने बताया था कि दुनिया के शीर्ष पांच प्रदूषित शहरों में पाकिस्तान के फैसलाबाद के अलावा भारत के चार शहर थे। शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में भारत के सात शहर थे। इसी तरह शीर्ष 30 प्रदूषित शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषित 22 शहर हमारे थे। ग्रीनपीस के एक और अध्ययन में यह पाया गया कि शुद्ध वायु के मामलों में भारत का एक भी शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंडों पर खरा नहीं उतर सका।

दिल्ली और आसपास के इलाके में फैलने वाले प्रदूषण के लिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जलाई जाने वाली पराली को जिम्मेदार बताया जाता है, मगर यह सिर्फ एक कारण है। वायु प्रदूषण के अन्य कारणों में बढ़ते वाहन, यातायात जाम, सड़कों और निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल और कल-कारखानों का धुआं भी है। दिल्ली में बाहर से आने वाले हजारों ट्रक यहां के हालात और भी गंभीर बनाते हैं। एक अनुमान के अनुसार दिल्ली की सड़कों पर रोज 40,000 लीटर ईंधन यानी पेट्रोल-डीजल महज यातायात जाम के कारण बर्बाद हो जाता है। जब कोई वाहन 40 किलोमीटर प्रति घंटे से कम गति पर चलता है तो उससे निकलने वाला प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है। बढ़ते प्रदूषण के जो भी कारण हैं उनके मूल में बढ़ती जनसंख्या है। जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान दिया ही जाना चाहिए। अगर यह सोचा जा रहा है कि केवल पराली दहन और पटाखों पर रोक लगाकर प्रदूषण से निपटा जा सकता है तो यह सही नहीं। पर्यावरण को सुधारने के उपायों के तहत कहीं न कहीं बढ़ती हुई जनसंख्या को भी नियंत्रित करने पर ध्यान देना होगा। बढ़ती आबादी केवल विकास के असर को ही कम नहीं करती, बल्कि प्रदूषण की समस्या को गंभीर बनाने का काम करती है।

प्रदूषण के चलते साइबेरिया सहित तमाम सुदूर देशों से आने वाले पक्षियों ने अब भारत से किनारा करना शुरू कर दिया है। दिल्ली स्थित यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के आंकड़े बताते हैं कि प्रवासी परिंदों की संख्या में पिछले कई वर्षों में लगातार कमी आई है। अगर यही हाल रहा तो परिंदे हमसे मुंह मोड़ लेंगे और यह बताने वाली बात नहीं कि यदि परिंदे पलायन की शुरुआत करते हैं तो सिलसिला इंसानों तक जा सकता है। वायु की खराब गुणवत्ता का सीधा रिश्ता दिल की बीमारी, फेफड़ों के कैंसर, दमा और सांस के रोगों से है। वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर हो रहा है। एक अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण छोटे बच्चों में डायबिटीज बढ़ती जा रही है। बच्चों में तो जन्म से पहले गर्भ में ही वायु प्रदूषण जनित मुश्किलें शुरू हो जाती है। साफ है कि प्रदूषण के मामले में केवल चिंता जताने का समय निकल गया है।

(लेखिका वेदार्णा फाउंडेशन की निदेशक हैं)

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग

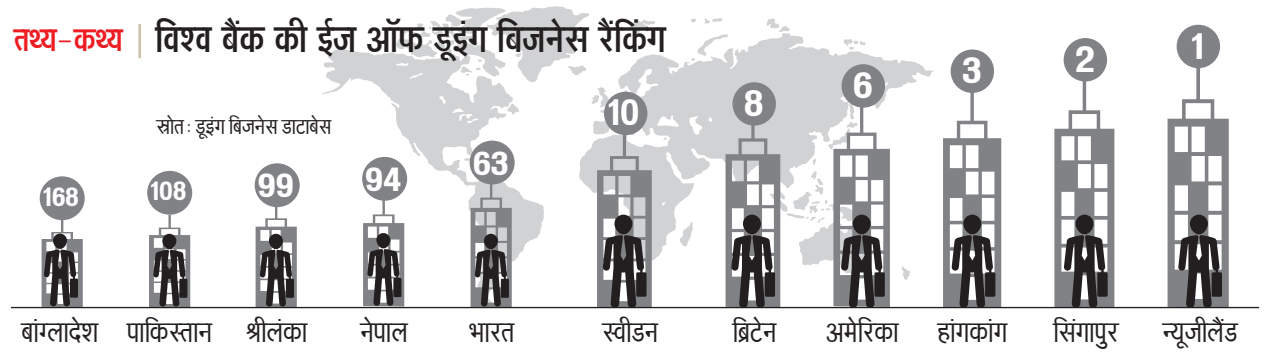

ऊर्जा

दीप जलाने का उद्देश्य

पूजा-पाठ में लोग सबसे पहले दीप-प्रज्वलित करते हैं, फिर अपने आराध्य देव की आरती करते हैं और अंत में कर्पूर से आरती करते हैं। इसमें संतुलित लौ होती है न कि भभकती आग होती है। इसी प्रकार मनुष्य को भी चाहिए कि वह संतुलित दीए की तरह बने। मनुष्य अपने जीवन में सरलता, सौम्यता, शुचिता, सत्यवादिता और मृदुता आदि को यदि अपनाता है तो वह पूजा-पाठ और आरती के दीए की तरह हो जाता है। आरती की लौ के प्रति जैसे पूजा-पाठ तथा धार्मिक अनुष्ठानों में लोग श्रद्धा प्रकट करते हैं और उसकी अग्नि को सिर-माथे लगाते हैं, उसी प्रकार इस तरह के व्यक्ति को घर-परिवार, पास-पड़ोस से लेकर हर जगह लोग श्रद्धा और सम्मान देते हैं। यही सब गुण मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम में था। उनका पूरा व्यक्तित्व प्रकाश फैलाने का था। दीपावली पर्व पर जलते ये संतुलित दीए सदाचार तथा सकारात्मकता का दीप बनने की शिक्षा देते हैं। दीपों की पंक्तियां देखने में भी आकर्षक लगती हैं। जबकि क्रोध, हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, संकीर्णता आदि भभकती आग की तरह हैं जो विनाशकारी होती है।

इस तरह की आग से जन-धन की हानि होती है और इसमें दूसरों से पहले जैसे अपना घर जलकर खाक होता है उसी प्रकार इस तरह के अनाचारी तथा नकारात्मक व्यक्ति का अपना पहले नुकसान होता है। इस तरह के व्यक्ति को लोग हेय दृष्टि से देखते हैं। इन्हीं कुप्रवृत्तियों के चलते रावण का वध हुआ। इस तरह के स्वभाव वाले लोगों का आत्मबल इतना गिरा रहता है कि यदि कोई सामान्य व्यक्ति इनको ललकार दे तो भयभीत हो जाते हैं। श्री राम और रावण की तुलना करते हुए तुलसीदास लिखते हैं-'रावण रथी, विरथ रघुबीरा।' यानी श्रीराम सामान्य व्यक्ति की तरह बिना रथ के पैदल हैं, जबकि रावण के पास तरह-तरह के अस्त्र-शस्त्र से लैस रथ थे, जिस पर सवार होकर वह चलता था, लेकिन कुप्रवृत्तियों के चलते वह पराजित होकर मारा गया। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपना व्यक्तित्व दीपावली के दीए जैसा बनाए जिससे लोकहित हो।

सलिल पांडेय

बढ़ती आबादी पर लगाम की कोशिश

देवेंद्र कुमार

> यह समझने की जरूरत है कि जनसंख्या को बढ़ाकर हम अपने आने वाले कल को ही खतरे में डाल रहे हैं

दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को भाजपा शासित राज्यों में धीरे-धीरे सभी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। इस कड़ी में असम सरकार ने सबसे पहले एक जनवरी 2021 के बाद दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है। असम से एक शुरुआत हुई है। इसमें भविष्य में चरणबद्ध तरीके कई राज्य साथ जुड़ेंगे और अपने यहां इससे मिलती जुलती नीति बनाएंगे। विभिन्न राज्य ऐसे मामलों में पहले सरकारी सेवा से वंचित करने के बाद दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को योजनाओं के लाभ से भी वंचित करेंगे। पार्टी शासित राज्यों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण पर लगाम की दिशा में इस तरह के फैसले करने के बाद केंद्रीय स्तर पर नई जनसंख्या नीति लागू करने पर उच्चस्तरीय विमर्श होगा।

दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यालय के पहले स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए दो बच्चों वाले परिवार को देशभक्त कहा था। तब कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार संभवतः निकट भविष्य में नई जनसंख्या नीति लागू करेगी। इस पर सरकार और पार्टी में गहन मंथन हुआ। तय हुआ कि सीधे नई जनसंख्या नीति लागू करने के बदले पार्टी राज्यों में अधिक बच्चे पैदा करने वालों को हतोत्साहित करने का फॉर्मूला तैयार करे। इसी के मद्देनजर सबसे पहले असम ने इस संदर्भ में फैसला लिया है। पार्टी के रणनीतिकारों को लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में इस तरह के फैसले से विपक्ष शासित राज्य भी दबाव में आएंगे। असम सरकार और भाजपा का फॉर्मूला कितना सटीक है, इस पर बहस की आवश्यकता है। मगर आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसे देखते हुए किसी एक फॉर्मूले पर सभी संगठनों, सरकारों एवं पार्टियों को एकराय बनानी होगी। बढ़ती आबादी न किसी एक राज्य की समस्या है और न ही किसी एक पार्टी की।

हमें समझना होगा कि अनियंत्रित गति से बढ़ रही जनसंख्या देश के विकास को बाधित करने के साथ ही हमारे आम जन जीवन को भी दिन-प्रतिदिन प्रभावित कर रही है। विकास की कोई भी परियोजना वर्तमान जनसंख्या दर को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, लेकिन अचानक जनसंख्या में इजाफा होने के कारण परियोजना का जमीनी धरातल पर साकार हो पाना मुश्किल हो जाता है। जाहिर है कि जैसे-जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ेगी, वैसे-वैसे गरीबी का रूप भी विकराल होता जाएगा। महंगाई बढ़ती जाएगी और जीवन के अस्तित्व के लिए संघर्ष होना प्रारंभ हो जाएगा। निःसंदेह जनसंख्या वृद्धि पर लगाम कसने का सबसे सरल उपाय परिवार नियोजन ही है। लोगों में जन-जागृति का अभाव होने के कारण दस-बारह बच्चों की फौज खड़ी करने में वे गुरेज नहीं करते हैं। इसलिए सबसे पहले उन्हें जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने की महती आवश्यकता है। यह समझने की जरूरत है कि जनसंख्या को बढ़ाकर हम अपने आने वाले कल को ही खतरे में डाल रहे हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

राष्ट्रीय मुद्दे उठाने से नहीं हुआ नुकसान

पक्ष-विपक्ष को आईना दिखाता जनादेश शीर्षक से लिखे अपने लेख में रशीद किदवई ने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों के परिणामों के आधार पर इन राज्यों विशेषकर हरियाणा में कांग्रेस नेतृत्व द्वारा समझदारी से लिए गए फैसलों की सराहना की है। उनका यह भी मानना है कि भाजपा की सरकारों द्वारा स्थानीय मुद्दों की उपेक्षा और राष्ट्रीय मुद्दों पर बल देने से उन्हें नुकसान हुआ है, लेकिन अगर चुनाव नतीजों पर गौर करें तो मोटे तौर पर जो बातें सामने आती हैं, वह यह है कि इस बार मतदान लोकसभा चुनावों में पड़े मतदान की अपेक्षा आठ फीसद कम रहा। इसके बावजूद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में गिरावट नहीं हुई है, बल्कि वह करीब तीन फीसद तक बढ़ी ही है। महाराष्ट्र में गठबंधन के कारण भाजपा इस बार पिछली बार की अपेक्षा काफी कम सीटों पर लड़ी, जिसकी वजह से वह त्रिकोणीय मुकाबलों से उठा सकने वाली संभावित लाभ से वंचित हो गई। लेखक ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में मराठों और हरियाणा में जाटों की उपेक्षा से भाजपा को नुकसान हुआ। मराठों अथवा जाटों की उपेक्षा से लेखक का क्या अभिप्राय है, यह उन्हें स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में इन वर्गों के प्रतिनिधियों को सरकार में अच्छा-खासा प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। यदि लेखक का इशारा मुख्यमंत्री पद पर इन वर्गों के लोगों को बैठाने से है तो सच्चाई यह है कि भाजपा ने ऐसा कर उक्त दोनों राज्यों में वहां की परंपरागत जातिवादी वर्चस्व को तोड़ने की कोशिश की है और इसमें कुछ भी गलत नहीं। यह सही है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा को आशानुरूप सीटें नहीं मिलीं। स्थानीय मुद्दे सदैव से राज्यों के चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन यह मानना कि राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने की वजह से दोनों राज्यों में भाजपा को नुकसान हुआ, सही नहीं होगा। एक तबका यह भी मानता है कि यदि अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों को न उठाया जाता और चुनाव की कमान स्वयं नरेंद्र मोदी और अमित शाह सरीखे दिग्गज राष्ट्रीय नेता न उठाते तो दोनों ही राज्यों में भाजपा की स्थिति शायद इससे भी कुछ कमतर रह सकती थी।

chandankarn9470@gmail.com

नतीजों से लें सबक

हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा के ताजा चुनावी परिणामों से एक बड़ा संदेश निकलकर आया है कि जागरूक जनता को सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पर ही आकर्षित नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ समय से अनुच्छेद 370, पुलवामा हमला, एयर स्ट्राइक व अन्य राष्ट्रीय मुद्दे शीर्ष पर थे। महाराष्ट्र व हरियाणा में सत्तारूढ़ दल ने भी राष्ट्रवाद के मुद्दों के इर्दगिर्द ही अपना सियासी स्टैंड रखा। विधानसभा चुनावों में जनता विकास संबंधी स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तरजीह देती है और यह चुनाव आम जनता से जुड़े हुए स्थानीय स्तर के मुद्दों पर ही लड़े जाते रहे हैं। सत्तासीन दल की सीटों में गिरावट का सबसे बड़ा कारण जनता के असल मुद्दों से भटकना ही रहा, जबकि विपक्ष ने परिस्थितियों को भांपकर जनता से जुड़े स्थानीय मामलों जैसे किसानों की समस्या, बेरोजगारी, मंदी, मंहगाई व विकास को चुनावी आधार बनाया। अभी दिल्ली, झारखंड और उसके बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। ताजा चुनावी नतीजों से सभी दलों को यह सबक लेना चाहिए कि राष्ट्रवाद को आधार बनाकर स्थानीय स्तर के मुद्दों की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

hitender.dedha@gmail.com

स्थाई सरकार की तमन्ना

जनमत बरसाती नदी के प्रवाह की तरह चंचल होता है। उसकी धारा कब और किधर चल पड़े इसका अनुमान तो राजनीति के पुरोधा भी नहीं लगा सकते। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सारे अनुमान धरे रह गए और जनमत ने राजनीति को अधर में लटका कर छोड़ दिया। इस चुनाव में 75 पार का सपना देखने वाली भाजपा केवल 40 सीटों पर सिमट कर रह गई। भाजपा को यह समझना चाहिए कि लक्ष्य निर्धारित करना जितना आसान है उसे पाना उतना ही कठिन होता है। चौधरी देवीलाल की विरासत संभालने वाली इनेलो के पिछली विधानसभा में 19 विधायक थे और वह मुख्य विपक्षी दल के रूप में थी, लेकिन इस बार इनेलो केवल एक ही सीट जीत सकी। इनेलो से अलग हुई जेजेपी भी दस सीटें ही जीत सकी। यदि इनेलो और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ते तो परिणाम बेहतर हो सकते थे।

रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प